The recommendations are to be implemented by the State Government of Andhra Pradesh and the Central Government Departments such as Posts and Telegraphs, Railways, All India Radio, India Meteorological Department, Civil Aviation and the Central Water and Power Commission. The recommendations have been forwarded to all concerned for examination and implementation.

सोन बैराज और कोयल नदी का जल

754. **श्री निरंजन वर्मा :**
श्री बलराम दास :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य की सरकार सोन बैराज के केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित क्षेत्र से आगे विस्तार करने का विचार कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार ने उत्तर कोयल नदी पर एक परियोजना के लिये एक प्रस्ताव भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†[SONE BARRAGE AND KOEL RIVER WATER

754. SHRI NIRANJAN VARMA :
SHRI BALRAM DAS :

Will the Minister of IRRIGATION AND POWER/**सिंचाई और विद्युत् मंत्री** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the state Government of Bihar, propose to extend the area under the Sone Barrage system beyond the area authorised by the Central Government;

(b) whether it is also a fact that the State Government have submitted a proposal for a project on the North Koel river; and

(c) if so, what is the reaction of the Government of India in this regard?]

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) (क) राज्य सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जी, हां।

(ग) सोन उच्च स्तरीय नहर क्षेत्रों की सप्लाई की अनुपूर्ति करने के अलावा उत्तरी कोयल परियोजना द्वारा नए क्षेत्रों की सिंचाई करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना की केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग में जांच हो रही है।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER/**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री** (SHRI BAIJ NATH KUREEL) : (a) No specific proposal from the State Government has been received.

(b) Yes.

(c) North Koel project proposes to irrigate new areas in addition to supplementing the supplies to the Sone High level Canal areas. The project is under examination in Central Water and Power Commission.]

बाण सागर परियोजना

755. **श्री निरंजन वर्मा :**
श्री बलराम दास :
श्री बी० एन० मंडल :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बिहार सरकार द्वारा उठाई गई कतिपय आपत्तियों के कारण बाण सागर परियोजना की स्वीकृति रोक दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस समय विवाद की क्या स्थिति है और इस विवाद को सुलझाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं, और

(ग) क्या बिहार सरकार इस मामले को उच्चतम न्यायालय में ले जाने का विचार कर रही है ताकि इस मामले पर उसके विचार जाने जा सकें। यदि हां, तो इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†[ ]English translation.

†[BANSAGAR PROJECT

755. SHRI NIRANJAN VARMA :
SHRI BALRAM DAS :
SHRI B. N. MANDAL :

Will the Minister of IRRIGATION AND POWER/**सिंचाई और विद्युत् मंत्री** be pleased to state :

(a) whether clearance of the Bansagar project is held up for certain objections raised by the Government of Bihar :

(b) if so, at what stage the dispute stands at present and what steps are being taken to resolve the dispute; and

(c) whether Bihar Government propose to take this issue to the Supreme Court for eliciting its opinion thereon; if so, the Union Government's reaction thereto ?]

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) और (ख) मध्यप्रदेश सरकार ने सोन नदी पर बाणसागर परियोजना को मध्यप्रदेश की विकास संबंधी योजनाओं में सम्मिलित करने हेतु योजना आयोग की स्वीकृति के लिए प्रस्तावित किया है।

बिहार सरकार ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा यथा प्रस्तावित बाणसागर परियोजना, जिसमें सोन के पानी को एक दूसरे बेसिन में टोंस नदी में व्यपवर्तित करने की बात है, का इस आधार पर विरोध किया है कि सोन के बहुत निचले भाग में, यहां पानी की सप्लाई की स्थिति पहले ही बहुत नाजुक बतायी जाती है, बिहार की बृहत् सिंचाई प्रणाली पर इस परियोजना का बुरा असर पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार इस बात का आग्रह करती रही है कि मिर्जापुर जिले में अकालग्रस्त पठारी क्षेत्रों की सिंचाई का एकमात्र साधन बाणसागर परियोजना है और इस क्षेत्र में भी सिंचाई की व्यवस्था की दृष्टि से मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित बाणसागर परियोजना में संशोधन किया जाए।

भारत सरकार ने इस दिशा में प्रयास किये हैं कि ऐसे प्रस्ताव लाये जायें जो तीनों राज्यों को स्वीकार्य हों।

पहली अगस्त, 1971 को केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत् मंत्री और बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्रियों की एक अंतर्राज्यीय बैठक भी हुई थी। विचार-विमर्श के बाद, अध्यक्ष, केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग और तीनों राज्यों के मुख्य इंजीनियरों की एक तकनिकी समिति ने इस संबंध में और विचार विमर्श किये। मुख्य मंत्रियों द्वारा इस मामले पर अभी और विचार किया जाएगा।

(ग) इस संबंध में भारत सरकार को बिहार सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER/**सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री** (SHRI BAIJ NATH KUREEL) : (a) and (b) The Madhya Pradesh Government have proposed the Bansagar Project on river Sone for acceptance by the Planning Commission for inclusion in the developmental plans of Madhya Pradesh.

The Government of Bihar have protested against the Bansagar Project as proposed by the Government of Madhya Pradesh involving diversion of the Sone waters to the Tons river in another basin, on the ground that it will affect the large irrigation system in Bihar from the Sone Lower down where the position of supplies is stated to be already critical.

The Government of Uttar Pradesh have been urging that the Bansagar Project is the only source of irrigation to the famine stricken plateau areas in Mirzapur district and that the Bansagar Project proposed by the Madhya Pradesh Government should be modified to make provision of irrigation in this area also.

Efforts have been made by the Government of India to evolve proposals which might be acceptable to the three States.

An Inter-State meeting was also held amongst the Union Minister of Irrigation and Power and the Chief Ministers of Bihar, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh on the 1st August 1971. Pursuant to the discussions a technical Committee comprising the Chairman, Central Water and Power Commission

†[ ]English translation.

and the Chief Engineers of the three States had further discussions. The matter will be further considered by the Chief Ministers.

(c) The Government of India have not received any intimation in this regard from the Government of Bihar]

WAGES PAID TO CASUAL WORKERS IN KOLLENGODE SECTION OF SOUTHERN RAILWAY

756 SHRI BALACHANDRA MENON Will the Minister of RAILWAYS/रेल मंत्री be pleased to state :

(a) what are the rates of wages paid to the casual workers of the Engineering Department in the Kollengode section of the Southern Railway ;

(b) what are the rates for corresponding jobs fixed by the local authorities, and

(c) what are the reasons for the difference in wage rates, if any ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय में उपमंत्री (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) and (b) A statement is attached.

(c) The standard rate fixed by local authority is without wages for rest days. Hence, the Railway rates have been adjusted proportionately as the casual labourers in Railways are entitled to wages for weekly rest days.

STATEMENT

Rates of Daily wages effective from 21st October, 1971 fixed for casual labourers on Kollengode section of the Southern Railway

Category	Rates fixed by the railway with wages for rest day	Rates fixed by local authorities:	
		Standard rate without wages for rest days	Proportionate rate with wages for rest days
	Rs.	Rs	Rs.
Mate	4.10	4 75	4.12
Man Khalasi	3 70	4 25	3.68
Woman Khalasi	3.00	3.50	3.03
Blacksmith (skilled)	5.20	6 00	5.20
Bricklayer (skilled)	6.10	7.00	6.07
Carpenter (skilled)	5.20	6.00	5.20
Painter (skilled)	4.80	5 50	4 77
Plumber (skilled)	5.00	5.75	4.98
Welder (skilled)	6.10	7.00	6.07